कार्यक्रम प्रायोजित किये । इनमें से चार कार्यक्रम कम्प्यूटरीकरण तथा एक वित्तीय प्रबंध से संबंधित था । कम्प्यटर प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने वाले एक प्रतिभागी ने प्रश्न के भाग "ख" में उल्लिखित कमियों की ओर ध्यान आकृष्ट करवाया । इसको देखते हुये तथा अन्य प्रमुख कम्प्यूटर प्रशिक्षण संस्थानों में उपलब्ध बेहतर सुविधाओं को देखते हुये 1993-94 तथा 1994-95 के अनुवर्ती वर्षों में इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउंटेंटस आफ इंडिया, नई दिल्ली को कोई भी कम्प्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम आबंटित नहीं किया गया ।

इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउटेंट्स आफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा केन्द्रीय सरकार के प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण पत्र दिया जाना

5977. **मौलाना अबदुल्ला खान आजमी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इडिया नई दिल्ली में केन्द्रीय सरकार के प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण पत्र दिया जाना मात्र उनकी उपस्थिति लगने पर निर्भर है न कि प्रशिक्षण के दौरान उन लोगों के वास्तविक रूप से उपस्थित रहने पर ;

(ख) क्या यह भी सच है कि वहां प्रशिक्षणार्थियों द्वारा उपस्थिति लगाने के लिये समुचित प्रबंध नहीं है और उनमें से जो वहां उपस्थित रहते हुए भी अपर्याप्त प्रबंध के कारण अपनी उपस्थिति नहीं लगा पाते हैं उन्हें मनमाने ढंग से प्रमाण-पत्र से वंचित कर दिया जाता है ;

(ग) यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या कदम उठा रही है ; और

(घ) इस संपूर्ण प्रक्रिया को वास्तविकता से जोड़ने के लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री श्रीमति मार्ग्रेट आल्वा : (क) और (ख) इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउटेंटस ऑफ इंडिया नई दिल्ली के अनुसार केन्द्रीय सरकार के प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण-पत्र का दिया जाना पाठ्यक्रम के दौरान उनका वास्तविक उपस्थिति पर निर्भर करता है। इंस्टीट्यूट द्वारा उन प्रतिभागियों की वास्तविक उपस्थिति सुनिश्चित करने पर पर्याप्त सावधानी बरती जाती है जो दिन के दौरान उपस्थिति लगा देते हैं। ऐसे प्रतिभागियों को पाठ्यक्रम समन्वयक की पूर्वानुमति प्राप्त किए बिना छुट्टी लेने की अनुमति नहीं दी जाती। उपस्थिति दिन में दो बार ली जाती है। इंस्टीटयूट द्वारा अपनाई जा रही इस पद्धति से कार्य संतोषजनक चल रहा है।

(ग) और (घ) उपर्युक्त (क) तथा (ख) के मद्दे नज़र प्रश्न नहीं उठता।

Implementation of Mandal Commission recommendations

5979. SHRI AHMED MOHMEDBHAI PATEL: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Gujarat is the first State in the country which has accepted the Supreme Court's verdict on Mandal Commission recommendations providing reservation in Government jobs for Backward communities.

(b) whether the State Government has also provided 17 per cent reservation in professional institutions such as Engineering and Medical Colleges;

(c) whether the State Government has also started implementing the said scheme from the 1st January, 1994;

(d) if so, the names of other States which have fully accepted the Mandal Commission recommendations; and

(e) whether any concrete information from State Governments has been received, if so, the details there. of?